

शाहजहां शेख पर ईडी का एशन, कई जगहों पर छापेमारी, सुरक्षाबलों ने इलाके को घेरा

निलंबित टीएमसी नेता शेख शाहजहां के खिलाफ जमीन हड़पने के मामले में ईडी पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में सुबह से कई स्थानों पर छापेमारी कर रही है

तेजयुग न्यूज

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में ईडी की टीम पर हमले के मास्टरमाइंड शाहजहां शेख पर शिकंजा कसता जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को शाहजहां शेख के संदेशखाली और उसके आस-पास के इलाकों में जमीन कब्जाने के मामले में छापेमारी की है।

ईडी ने इस मामले में पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया है। कई जगहों पर यह छापेमारी की गई है। ईडी की टीम संदेशखाली में शाहजहां के अलावा, उसके

कई करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। शाहजहां शेख के खिलाफ जमीन हड़पने और महिलाओं के यौन उत्पीड़न का आरोप है। ईडी को शाहजहां शेख से

पृच्छाछ में आर्थिक लेनदेन की जानकारी मिली है। इसी सिलसिले में यह छापेमारी हो रही है। इस दौरान भारी संख्या में सुरक्षाबलों की टीम मौजूद है। सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है।

जमीनों को कब्जाने और राशन घोटाला मामले में छापेमारी: शाहजहां शेख पर संदेशखाली और उसके आस-पास जमीनों को कब्जाने और राशन घोटाला मामले में छापेमारी की गयी है। राशन घोटाला मामले में ईडी अधिकारियों ने बड़ी संख्या में केंद्रीय बलों की मौजूदगी में उत्तर 24 परगना जिले

ईडी की टीम पर शाहजहां के समर्थकों का हमला

इससे पहले संदेशखाली में 5 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर भीड़ के हमले के संबंध में छद्म ने तृणमूल कांग्रेस के निलंबित नेता शाहजहां शेख के भाई और उनके कुछ करीबियों को पृच्छाछ के लिए तलब किया था। संदेशखाली में हुई हिंसा से पहले जनवरी में ईडी की टीम राशन घोटाला मामले में छापेमारी के लिए शाहजहां शेख के ठिकानों पर पहुंची थी। इस दौरान ईडी की टीम पर शाहजहां के समर्थकों ने हमला कर दिया था। छापेमारी करने पहुंची टीम पर 3000 लोगों की भीड़ ने हमला किया था। इसमें कई अधिकारियों को चोटें भी आई थीं। शाहजहां को इस हमले के लिए मास्टरमाइंड माना जा रहा है लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि उसने ये काम अकेले अंजाम नहीं दिया होगा। इस मामले की जांच अब सीबीआई कर रही है। अदालत के फैसले के बाद शाहजहां शेख की कस्टडी के साथ-साथ ईडी पर हमले के केस को भी सीबीआई को ट्रांसफर किया गया। जिसके बाद सीबीआई ने शाहजहां के भाई आलमगीर शेख को समन किया है। माना जा रहा है कि सीबीआई की टीम शाहजहां शेख के भाई आलमगीर से ईडी टीम पर हुए हमले को लेकर पृच्छाछ करने वाली है।

के रामपुर में कई मछली व्यापारियों के यहां छापेमारी की है। ये व्यापारी सीबीआई की कस्टडी में मौजूद शाहजहां शेख के करीबी हैं।

हापड़

पारा अपडेट

मैक्सिमम

मिनीमम

22.00 °C

11.00 °C

सूर्यास्त (आज) >> 17.10 बजे

सूर्योदय (कल) >> 06.25 बजे

सरकार ने अश्लील विषय वस्तु का प्रसारण करने वाल 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया

नयी दिल्ली: सरकार ने अश्लील विषय वस्तु और सामग्री का प्रसारण करने वाले 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने गुरुवार को एक वक्तव्य जारी कर कहा कि इन प्लेटफॉर्म के साथ साथ 19 वेबसाइटों, 10 ऐप जिनमें से सात गुगल प्ले स्टोर पर और तीन एप्पल ऐप स्टोर पर हैं और इनसे जुड़े 57 सोशल मीडिया अकाउंट पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने रचनात्मक अभिव्यक्ति को आड़ में अश्लीलता और दुर्व्यवहार का प्रचार न करने के लिए प्लेटफॉर्म को जिम्मेदारी पर बांध-बांध जोर दिया है। उन्होंने मंगलवार को घोषणा की थी कि अश्लील सामग्री प्रकाशित करने वाले 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म को ब्लॉक किया जा रहा है। यह निर्णय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, मीडिया, मनोरंजन, महिला अधिकारों और बाल अधिकारों के क्षेत्र में विशेषज्ञों के परामर्श से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के तहत लिया गया है।

लेखिका सुधा मूर्ति ने राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली, धनखड़ ने सदस्यता की शपथ दिलाई

नयी दिल्ली: हाल ही में उच्च सदन के लिए मनोनीत की गई सामाजिक कार्यकर्ता, इंजीनियर और जानीमानी लेखिका सुधा मूर्ति ने गुरुवार को राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने श्रमती मूर्ति को राज्यसभा की सदस्यता की शपथ दिलाई। इस मौके पर नेता सदन पीयूष गोयल, राज्यसभा के महासचिव पी सी मोदी और अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। आठ मार्च को महिला विक्स के मौके पर उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था।

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया चार सौ सीट जीतने का दावा

विशेष अधिकार वाले क्षेत्रों में सीएए लागू नहीं: अमित शाह

तेजयुग न्यूज

गुवाहाटी : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) पूर्वोत्तर क्षेत्रों में लागू नहीं किया जाएगा जहां विशेष अधिकार दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सीएए का राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) से कोई संबंध नहीं है और इसे असम और देश के अन्य हिस्सों में लागू किया जाएगा। सीएए से बूट वाले क्षेत्र वे हैं जहां इनर लाइन परमिट (आईएलपी) का प्रावधान है

● असम में यह कानून पूरी तरह महत्वहीन: हिमंत बिस्वा सरमा

● भाजपा की अगुवाई में 13 सीटें यहां से जीतेगा एनडीए

और जिन्हें संविधान की 6वीं अनुसूची के तहत विशेष दर्जा दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया है कि मुस्लिम नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

मुसलमानों को भी नागरिकता के लिए आवेदन करने का अधिकार है किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं किए गए हैं। यथा विशेष अधिनियम इसलिए बना गया है क्योंकि लोग बिना किसी दस्तावेज के आए हैं...हम उन लोगों के लिए रास्ता खोजेंगे जो ऐसा करते हैं। आवेदन करने के लिए समय ले सकते हैं, भारत सरकार आपको उपलब्ध समय के अनुसार साक्षात्कार के लिए बुलाएगी। सरकार

करीगे दस्तावेज के ऑडिट के लिए आपको बुलाया जाएगा और अगले सामने साक्षात्कार किया जाएगा...उन सभी लोगों का यहां स्वागत है जो 15 अगस्त 1947 से 31 दिसंबर 2014 के बीच भारत में आए हैं।

हालांकि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार को दावा किया कि असम में सीएए पूरी तरह से महत्वहीन है, जहां से भारतीय नागरिकता के लिए सबसे कम संख्या में आवेदन आएंगे। सरमा ने कहा कि अधिनियम बहुत स्पष्ट है कि नागरिकता के आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2014 है और असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के अद्यतनीकरण के साथ, इन लोगों ने इसके लिए आवेदन किया था और उनका नाम उसमें नहीं था। सीएम ने यह भी कहा कि भाजपा असम की 14 लोकसभा सीटों में से 13 सीटें जीतेगी।

सरमा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के बाद तीसरे कार्यकाल के लिए लौटेंगे। गुवाहाटी

के लोक सेवा भवन में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल का जवाब देते हुए असम के सीएम ने कहा कि पहले वह कहते थे कि असम में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए की संख्या 11 होगी, लेकिन कांग्रेस द्वारा अपनी सूची की घोषणा के बाद उम्मीदवारों, मुझे पूरा यकीन है कि, हम इस बार 13 सीटें जीतेंगे। हम बुकरी सीट नहीं जीत पाएंगे।

उन्होंने आगे कहा कि डिब्रूगढ़ सीट पर सबानंद सोनोवाल तीन लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीतेंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगामी चुनाव में एनडीए सरकार के एकबार फिर सत्ता में आने का दावा किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में एनडीए 400 से अधिक सीटें जीतकर सत्ता में वापस लौटेगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटती है तो सभी को पक्का आवास मिलेगा।

मोदी की कमेटी ने दो चुनाव आयुक्तों का चयन किया

असहमति का नोट दिया है विपक्ष के नेता अधीर रंजन ने

तेजयुग न्यूज

नई दिल्ली: लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने आज दोपहर मीडिया को बताया कि नौकरशाही सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार को भारत के चुनाव आयोग के शीर्ष पैनल में दो रिक्त पदों के लिए चुना गया है।

● पैनल में मोदी और अमित शाह थे

● सरकार जो चाहती है वही होता है

● सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी

श्री चौधरी प्रधान चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की सहायता के लिए दो चुनाव आयुक्तों का चयन करने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले पैनल का हिस्सा थे, क्योंकि चुनाव निकाय आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहा था। प्रधानमंत्री और श्री चौधरी के अलावा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पैनल में थे। कांग्रेस नेता

जांच के लिए 212 नाम दिए गए थे। मैंने एक शॉर्टलिस्ट मांगी थी ताकि मैं उम्मीदवारों की जांच कर सकूँ। लेकिन मुझे वह मौका नहीं मिला। मैं आधी रात को दिल्ली पहुंचा और आज दोपहर को बैठक थी। मुझे 212 नाम दिए गए थे, कोई इतने सारे उम्मीदवारों की जांच एक दिन में कोई कैसे कर सकता है। बैठक से दस मिनट पहले, मुझे 6 नामों की एक शॉर्टलिस्ट दी गई, उन्होंने कहा। यह तय

था कि चुने गए दो लोगों का चयन किया जाएगा। हालांकि, मैंने संस्थान को मजबूत करने के लिए उचित तरीके से हस्तक्षेप करने की कोशिश की। इसलिए, दिल्ली पहुंचने से पहले, मैंने एक शॉर्टलिस्ट मांगी। उन्होंने मुझे एक सूची दी सभी 212 उम्मीदवारों की सूची। कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्होंने चयन की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए एक असहमति नोट दिया है। श्री चौधरी ने चुनाव आयुक्त के पद से अरुण गोयल के इस्तीफे का भी जिक्र किया, जिससे विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा, जब श्री गोयल को नियुक्त किया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बिजली की गति से आए और डिजिटल गति से चले गए। चुने गये नये चुनाव आयुक्तों में श्री संधू और श्री कुमार 1988 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। जहां श्री संधू आईएएस के उत्तराखंड कैडर से हैं, वहीं श्री कुमार केरल कैडर से हैं।

कड़ाके की ठंड के बीच लगातार अनशन कर रहे हैं वांगचुक, कहा लद्दाख को अधिकारियों ने उपनिवेश बना दिया है

तेजयुग न्यूज

श्रीनगर: नक्सलवादी और लद्दाखी मैसैसे बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर 3 इंडियन्स में पुरस्कार प्राप्तकर्ता सोनम वांगचुक, जो लद्दाख को विशेष दर्जा और राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर हैं, ने मंगलवार को कहा कि लद्दाखियों को अब यह महसूस होता है कि [लद्दाख] पुराने समय में एक कॉलोनी की तरह है और दूर-दूर से अधिकारी आते हैं। उन पर शासन

करने के लिए। वांगचुक, जिन्हें जीवन ने बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर 3 इंडियन्स में अमिर खान द्वारा निभाए गए पुनर्मुख वांगडू के चित्रण की प्रेरित किया, भारत के संविधान की छठी अनुसूची के तहत केंद्र शासित प्रदेश की विशेष स्थिति के लिए दबाव डालने के लिए, ठंड के बीच 21 दिन का उपवास कर रहे हैं। और राज्य का दर्जा। लद्दाख को पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर से अलग करने और

2019 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिए जाने के बाद ये मांग क्षेत्र की राजनीति पर हावी हो गई हैं। उन्होंने 6 मार्च को तब अनशन शुरू किया जब लद्दाख के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्रालय के बीच बातचीत गतिरोध पर पहुंच गई, जब एक्स बॉडी लेह (एबीएल) और कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस (केडीए) ने कहा कि उप-समिति स्तर की बातचीत और उनकी अलग बैठक होगी।

हैदराबाद पुलिस ने निलंबित अधिकारी को गिरफ्तार किया

तेजयुग न्यूज

हैदराबाद: हैदराबाद पुलिस ने बुधवार को एक निलंबित पुलिस उपाधीक्षक को गिरफ्तार किया, जिस पर तेलंगाना में पार्टी के सत्ता में रहने के दौरान भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के राजनीतिक विरोधियों के फोन टैप करने का संदेह है। जब कथित अपराध हुए थे तब डीएसपी दुयाल प्रणीत कुमार एसआईबी में तैनात थे। पिछले साल कांग्रेस के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद एसआईबी की हार्ड ड्राइव से कथित तौर पर खुफिया डेटा मिटाने की बात सामने आने के बाद उन्हें इस महीने की शुरुआत में निलंबित कर दिया गया था। उन पर खुफिया डेटा को अपने निजी उपकरणों में कॉपी करने का भी आरोप है। उन पर पिछले हफ्ते सबूतों के साथ छेड़छाड़,

विश्वास का उल्लंघन और आपराधिक साजिश के आरोप में मामला दर्ज किया गया था।

अधिकारियों ने बताया कि कुमार को मंगलवार रात हिरासत में लिया गया और रात भर पृच्छाछ के बाद बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया। सुर्जों के मुताबिक, कुमार पर बीआरएस के सत्ता में रहने के दौरान विपक्षी नेताओं और अन्य लोगों के फोन टैपिंग में शामिल होने का संदेह है। एसआईबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डी रमेश ने कुमार के खिलाफ पहली शिकायत यह पता लगाने के बाद दर्ज की थी कि वह 2018 और 2023 के बीच कथित फोन टैपिंग और डेटा की नकल में शामिल थे। कुमार नियमित रूप से अपने व्यक्तिगत पेन ड्राइव पर खुफिया डेटा की प्रतिलिपि बनाते थे, और उन पर इसका उपयोग करने का संदेह है।

पांच हजार करोड़ से जरूरतों पूरी नहीं होती केरल सरकार ने केंद्र सरकार का प्रस्ताव ठुकराया

तेजयुग न्यूज

तिरुअनंतपुरम : केंद्र सरकार ने 13 मार्च को कहा था कि वह केरल में तत्काल वित्तीय संकट को रोकने के लिए एकमुश्त उपाय के रूप में केवल 5,000 करोड़ ही छोड़ सकती है, जिसके बाद केंद्र और केरल के बीच सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई का बिगुल बज गया है।

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और सी.के. विश्वनाथन ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा दी गई राशि पेंशन और वेतन सहित केरल की सबसे बुनियादी वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे शशी विश्वनाथन ने जस्टिस सूर्यकांत और के.वी. की खंडपीठ को बताया। केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि वह वित्तीय वर्ष 2024-2025 के पहले नौ महीनों में राज्य की शुद्ध उधार सीमा से ?5,000 करोड़ की कटौती करेगी, और शर्त लगाई कि राज्य को 2024-2025 में किसी भी तदर्थ उधार की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसमें अभी प्रस्तावित 5,000 करोड़ की आवश्यकता है। श्रीमान सिब्बल ने कहा कि केंद्र सरकार का उद्देश्य केवल राज्य को दबाना और उसके वित्त को नियंत्रित करना था। केंद्र की पेशकश को खारिज करते हुए

उन्होंने कहा, 'हम कम से कम 10,000 करोड़ रुपये चाहते हैं। यह 5,000 करोड़ हमें कहीं नहीं ले जाता। सरकार इस कम राशि से लोगों को भुगतान नहीं कर पायेगी। अदालत केरल द्वारा दायर एक मूल मुकदमे पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केंद्र सरकार पर संघवाद के सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए उसकी उधार सीमा और वित्तीय मामलों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया गया था।

इससे पहले की सुनवाई में जस्टिस कांत ने कहा था कि यह मुकदमा संभवतः सुप्रीम कोर्ट में अपनी तरह का पहला मामला है। अदालत ने मामले को अंतरिम राहत के लिए दलीलें सुनने के लिए 21 मार्च को सुचीबद्ध किया है। बेंच ने शुरू में केंद्र और राज्य सरकारों से इस मुद्दे को अदालत के बाहर हल करने का आग्रह किया था। हालांकि, बुधवार की सुनवाई में सौहार्दपूर्ण समाधान की कोई भी उम्मीद धूमिल होती दिखाई दी क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन. वेंकटरमन ने एक नोट पढ़ा जिसमें सांख्यिकीय अनुमानों और केरल की वित्तीय मदद सीमित करने के कारणों का विवरण दिया गया था।

अफगानिस्तान में भारी बारिश और ठंड के कारण जनजीवन तबाह बांमियान के इलाके में साठ लोगों की मौत

तेजयुग न्यूज

काबुल: अफगानिस्तान में पिछले तीन हफ्तों में भारी बारिश और ठंडे मौसम का सामना करना पड़ा है, जिसके परिणामस्वरूप कम से कम 60 लोगों की मौत हो गई और 23 घायल हो गए। देश के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बुधवार को बताया कि 1,645 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, और लगभग 200,000 पशुधन भी मारे गए हैं।

अपेक्षाकृत गर्म सर्दियों के बाद, देश में भारी बर्फबारी और बारिश हो रही है। इससे पहले फरवरी में, नूरिस्तान प्रांत के एक पहाड़ी गांव में हिमस्खलन हुआ, जिसमें कम से कम 21 लोग मारे गए। इसके अलावा, देश के उत्तरी प्रांतों को राजधानी काबुल से जोड़ने वाला सालांग दर्रा कई दिनों से भारी बर्फबारी के कारण अवरुद्ध हो गया है। अन्य प्रांतों में भी कई सड़कें बंद

हैं। अफगानिस्तान दशकों के संघर्ष और बाढ़ और भूकंप सहित एक के बाद एक प्राकृतिक आपदाओं के परिणामों से जूझ रहा है, जिसके परिणामस्वरूप हजारों मौतें हुई हैं। देश भर में मौसमी बाढ़ और हिमस्खलन समस्याएं होते रहते हैं, जिससे घरों, कृषि भूमि और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचता है। इस बार हादसे का केंद्र बांमियान है जो काबुल से लगभग 200 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में, मध्य अफगानिस्तान से

100 किलोमीटर तक फैली एक गहरी हरी और हरी-भरी घाटी में स्थित है, पूर्व सिल्क रोड पर, जो कभी चीन को मध्य एशिया और उससे आगे से जोड़ता था।

2001 के अंत में अमेरिकी नेतृत्व वाले अक्रम में उनके शासन को उखाड़ फेंकने से कुछ महीने पहले, तालिबान द्वारा नष्ट किए जाने से पहले यह शहर लगभग 2,000 साल पुरानी बुद्ध की दो मूर्तियों का घर था। बांमियान के मुख्य निवासी हजारों हैं।